

मुख्यमंत्री के अलवर-भरतपुर रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी

कांग्रेस की तरह समय खराब नहीं किया, दो माह में निकाय-पंचायत चुनाव हो जाएंगे- भजनलाल

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर, 7 सितंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को अलवर और भरतपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया।
बाजारों से जब मुख्यमंत्री का काफिला निकला तो लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने “वन स्टेट-वन इलेक्शन” को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और भाजपा के कार्यकाल की तारीफ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 2 माह में निकाय और पंचायतों के चुनाव एक साथ हो जाएंगे, हमने कांग्रेस की तरह जनता का समय खराब नहीं किया।
अलवर में हैलीपैड पर केन्द्रीय मन्त्री भूपेन्द्र यादव, वन मंत्री संजय शर्मा, पूर्व सांसद डॉ. कर्ण सिंह यादव व अन्य नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को अलवर के प्रमुख बाजारों में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया।

शहर के प्रमुख मंदिर श्री जगन्नाथजी महाराज के चरणों में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने शहर में एक रोड शो निकाला।
मुख्यमंत्री का काफिला जब

अलवर के प्रमुख बाजारों से गुजरा तो लोगों ने फूल बरसाए। इसी दौरान वन राज्य मंत्री की अचानक तबियत खराब हो गई, जिसके चलते वे कुछ समय के लिए गाड़ी में ही बैठ गए।

■ दोनों शहरों के प्रमुख मार्गों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रोड शो के दौरान लोगों ने फूल बरसा के स्वागत किया।

इसी तरह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर में नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो निकाला। यहाँ भी मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में आमजन उमड़े और जगह-जगह पुष्पवर्षा कर उनका अभिनंदन किया।
रोड शो के बाद मुख्यमंत्री ने भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली तथा सभी से एकजुट होकर भाजपा प्रत्याशियों को जिताने एवं सभी निकायों में भाजपा का बोर्ड बनाने का आह्वान किया।

राहुल गांधी ने राज्यों के प्रभारी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
कि अधिकार मिलने पर वे उसी तरह की गुटबाजी को नियंत्रित कर सकते हैं, जिसका उन्हें खुद सामना करना पड़ा था।
पंजाब से जुड़ा एक और दिलचस्प पहलू है। पायलट के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के साथ लंबे समय से अच्छे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। 2021 में अमरिंदर को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद, घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू हुई, जिसके अंत में चर्ची मुख्यमंत्री बने और 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई।
अमरिंदर अब कांग्रेस में नहीं हैं, इसलिए उनके साथ पायलट के संबंध से संगठन के स्तर पर पायलट को सीधे बहुत फायदा नहीं मिलेगा। अगर पायलट की जिम्मेदारी एक परीक्षा है, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला की जिम्मेदारी भरोसे का प्रमाण है।

सुरजेवाला उस समय एआईसीसी के प्रभारी थे, जब कांग्रेस ने 2023 में कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 135 सीटें जीती थीं। इस जीत के बाद मुख्यमंत्री चुनने का मुश्किल सवाल सामने आया था कि सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार में से किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। तीन साल बाद दूसरा और उससे भी ज्यादा संवेदनशील बदलाव तब हुआ, जब सिद्धारमैया ने पद छोड़ा और शिवकुमार ने इस साल 3 जून को मुख्यमंत्री पद संभाला। सुरजेवाला इस बदलाव को संभालने में भी गहराई से शामिल थे। इसी रिकॉर्ड से समझ आता है कि हाईकमान ने उन्हें कर्नाटक से नहीं हटाया और उनके पास गुजरात की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दे दी।
गुजरात में सुरजेवाला की जिम्मेदारी कर्नाटक से काफी अलग है। उन्हें 2027 के चुनाव से पहले कमजोर राज्य संगठन को ऐसी स्थिति में लाना

है, जिससे वह संभावित सरकार की तरह दिखाई दे। बघेल का पंजाब से असम जाना अलग तरीके से देखा जाना चाहिए।
बघेल ने असम के लगातार दो विधानसभा चुनावों में काम किया है। 2021 में उनकी छत्तीसगढ़ टीम को बृथ स्तर की तैयारियों और संगठनात्मक प्रशिक्षण के लिए बड़े पैमाने पर लगाया गया था। 2026 में वे कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षकों में से एक के रूप में फिर असम गए। अब प्रभारी महासचिव के रूप में उनकी नियुक्ति से उन्हें उस संगठन की औपचारिक जिम्मेदारी मिल गई है, जिसे वह पहले से जानते हैं। इससे असम में प्रियंका की भूमिका भी मजबूत होती है।
छत्तीसगढ़ के नए प्रभारी सुखदेव भगत झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी और आदिवासी नेता हैं। वे वर्तमान में

अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोहरदगा लोकसभा सीट से सांसद हैं। झारखंड से एक आदिवासी नेता को आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ भेजना कोई संयोग नहीं है। यह आदिवासी प्रतिनिधित्व पर राहुल के व्यापक जोर के अनुरूप है। सिरीवेल्ला प्रसाद की महाराष्ट्र में नियुक्ति ज्यादा चौंकाने वाली है।
आंध्र प्रदेश के इस नेता ने तमिलनाडु और झारखंड समेत कई राज्यों में एआईसीसी सचिव और सह-प्रभारी के रूप में काम किया है, लेकिन महाराष्ट्र उनके लिए राजनीतिक रूप से काफी बड़ी जिम्मेदारी है। प्रसाद महाराष्ट्र की स्थानीय गुटबाजी से जुड़े नहीं हैं, जो उनके लिए फायदे की बात हो सकती है। वे किसी मौजूदा गुट का हिस्सा बने बिना हाईकमान के प्रतिनिधि के रूप में काम कर सकते हैं। पी.वी. मोहन का आंध्र प्रदेश जाना भी इसी तरह की स्थिति

जर्मनी के चुनाव में “नैशनलिज़्म” की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
और कहते हैं कि नाज़ी दौर से उनका कोई लेना-देना नहीं है। आज के जर्मनों को अपराधबोध और अपने देश को लेकर शर्म की भावना से दबे रहने की ज़रूरत नहीं है।
जीतने वाली पार्टी के नेता ने कहा है कि “नैशनल प्राइड दुनिया की सबसे सामान्य चीज है” और यह भावना जर्मनी में वापस आनी चाहिए।
इस जीत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पहली बार किसी कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी ने ऐसी जीत हासिल की है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जर्मनी की राजनीति की पूरी बुनियाद की बुराई करती है और उसे गलत साबित करती है।
जर्मनी की मुख्यधारा की सभी राजनीतिक पार्टियों ने 1930 के दशक के जर्मन इतिहास, नाज़ी शासन और उसकी नीतियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की मुख्यधारा की राजनीति पर राष्ट्रीय अपराधबोध की भावना हावी रही, जो राष्ट्रीय गौरव को नकारने जैसा था।
एएफडी इन सभी से इनकार करती है और कहती है कि राष्ट्रीय गौरव जायज़ है और देश की पहचान का ज़रूरी हिस्सा है। बीबीसी ने सैक्सोनी-आनहाल्म में पार्टी के एक समर्थक के हवाले से कहा, जर्मनी विचारकों और कवियों का देश है। इसलिए नाज़ी दौर के नरसंहार और

युद्ध के इतिहास को लेकर शर्म से दबे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है।
प्रेक्टिकल पॉलिटिक्स में एएफडी “जर्मनी जर्मनों के लिए” थीम के साथ “रीमाइग्रेशन” की एक नई सरकारी पॉलिसी का प्रस्ताव कर रही है। राजनेता यह सोच रहे हैं कि क्या इसका मतलब बड़े पैमाने पर लोगों को देश से बाहर भेजना है। यह जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल की नीतियों को पलटने का संकेत है। मर्केल ने सीरिया में युद्ध से भाग रहे शरणार्थियों के लिए जर्मनी की सीमाएं खोल दी थीं।
मर्केल का फैसला वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चली आ रही जर्मनी की उदार प्रवासन नीति की ही एक कड़ी था।
युद्ध ने जर्मनी की काम करने की उम्र वाली आबादी के एक बड़े हिस्से को खत्म कर दिया था। युद्ध के बाद की सरकारों ने काम करने के लिए लोगों को, खास तौर पर तुर्की से, बड़ी संख्या में आने की अनुमति दी थी। इन लोगों को “गेस्ट वर्कर”, यानी अतिथि श्रमिक कहा जाता था। इनमें से बहुत से अतिथि श्रमिक और उनके बच्चे जर्मन समाज में घुल-मिल गए।
इस संवाददाता को 1984 में पूर्वी जर्मनी के कई क्षेत्रों को अपनी यात्रा याद है। यह यात्रा कई महीनों तक चले एक स्टडी प्रोग्राम और पश्चिम बर्लिन में रहने के दौरान की गई थी। उस समय का पूर्वी

जर्मनी, जो पूर्व सोवियत संघ के कम्युनिस्ट शासन के अधीन था, पश्चिमी जर्मनी की तुलना में निश्चित रूप से एक जर्जर, गरीब और बदहाल देश लगता था।
बाद में कई बार, इस देश की यात्रा के दौरान, जो अब एकजुट जर्मनी बन चुका था, इस संवाददाता ने एक नई वास्तविकता देखी। पूर्वी जर्मनी के वे लोग जो कभी समृद्ध और अधिक स्वतंत्र पश्चिमी हिस्से में जाने को कोशिश करते रहते थे, अब पुरानी यादों में जी रहे थे। पूर्वी जर्मनी के लोगों को ऐसा महसूस होने लगा था कि उनके साथ दूसरे दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार हो रहा है। वे लोग पूर्वी जर्मनी के उन दिनों की याद कर रहे थे, जब ज़िंदगी ज्यादा सुरक्षित थी, भले ही वे उतने अमीर नहीं थे।
इस संवाददाता को दिल्ली में पूर्वी जर्मनी का प्रतिनिधित्व करने वाले एक जर्मन राजनयिक मित्र की भी याद है। जब पूर्वी जर्मनी में उनके गृह नगर में उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने उन्हें बहुत साधारण और आर्थिक तंगी वाली ज़िंदगी जीते हुए पाया। इसके मुकाबले दिल्ली में उनके पास एक बड़ा बंगला, कई कर्मचारी और राजनयिक कार थी। अपने देश में वे लगातार ही रही बारिश से बचने के लिए सिर्फ एक छाता रख सकते थे और आने-जाने के लिए यू-बान, यानी भूमिगत मेट्रो का

इस्तेमाल करते थे। एक स्थानीय कंपनी में छोटी-सी नौकरी से उनका गुजारा चलता था।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पूर्वी जर्मनी के लोग अब ए.एफ.डी. पार्टी को सत्ता में ला रहे हैं। यह आम जर्मन लोगों की तरफ से नौकरी, जीवन और अपनी मूल जर्मन पहचान को बनाए रखने की कोशिश है।
‘लगता है ...
(प्रथम पृष्ठ का शेष)
स्थगित कर दिया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि नई प्रक्रिया पूरी होने तक खनन की कोई नई अनुमति या मौजूदा पट्टों का नवीनीकरण नहीं किया जाए।
उच्चस्तरीय समिति का गठन मई में कहीं ज्यादा व्यापक जिम्मेदारियों के साथ किया गया था। उसे अरावली के पूरे क्षेत्र का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने, एक समान परिभाषा सुझाने और खनन तथा विकास कार्यों के पर्यावरणीय और अन्य प्रभावों का आकलन करने की जिम्मेदारी दी गई थी।
समिति ने 28 फरवरी 2027 तक का समय मांगा था। उसका कहना था कि इस काम के लिए अतिरिक्त आंकड़ों, क्षेत्र में जाकर उनकी पुष्टि करने, विशेष विश्लेषण क्षमता और विशेषज्ञों की राय की ज़रूरत है।

राहुल की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
आगामी दौरे की तैयारियां चल रही थीं और बघेल इन तैयारियों की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहे थे। लेकिन अब उन्हें हटा कर हाईकमान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अंतिम फैसला लेने का अधिकार केवल उसी के पास है। इस कदम से चर्चा खेमे को यह संदेश भी दिया गया है कि बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है तथा इसलिए उसकी हर बात को अनिश्चित समय तक सहन नहीं किया जाएगा।
बघेल को हटाकर हाईकमान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राजा वर्डिंग का पद भी अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इससे ये अटकलें शुरू हो गई हैं कि क्या राहुल गांधी के पंजाब दौरे से पहले एक और बड़ा फेरबदल हो सकता है? पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि यह संभव है कि राजा वर्डिंग को दिल्ली बुलाया जाए और वहां उन्हें कोई विशेष जिम्मेदारी दे दी जाए।



आवेदन के लिए यशुआर स्कैन करें



भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग, कॉरपोरेट केंद्र, मुंबई

फ़ोन: 022-22820427

संविदा आधार पर विशेषज्ञ संवर्ग अधिकारियों की भर्ती

संविदा आधार पर निम्नलिखित पद के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

विज्ञापन सं.: CRPD/SCO/2026-27/21 (संविदा पद)		
पद का नाम	रिक्ति	आयु (31.08.2026 तक) अधिकतम
ग्रुप सीआईएसओ (मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी)	1	57 वर्ष

पात्रता मानदंड (आयु, अनुभव, जॉब प्रोफाइल आदि), रिक्ति विवरण, आवश्यक शुल्क एवं अन्य विवरण के लिए बैंक की वेबसाइट <https://sbi.bank.in/web/careers/current-openings> पर लॉग ऑन करें, जहाँ उपरोक्त विस्तृत विज्ञापन उपलब्ध हैं. इसके साथ आवेदन को ऑनलाइन जमा करने और साथ ही साथ आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने हेतु एक लिंक भी दी गई है. आवेदन करने और शुल्क भेजने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित करने एवं अन्य विवरणों के लिए विस्तृत विज्ञापन पढ़ें. कोई अन्य पुष्टताष्ट करने के लिए कृपया “CONTACT US”--> “Post Your Query” लिंक के माध्यम से हमें लिखें, जो कि बैंक की वेबसाइट (<https://sbi.bank.in/web/careers/post-your-query>) पर उपलब्ध है.

• आवेदन ऑनलाइन जमा करने और शुल्क का भुगतान करने की तिथि : 04.09.2026 से 24.09.2026 तक.

स्थान: मुंबई

दिनांक: 04.09.2026

महाप्रबंधक (आरपी एंड पीएम)



MARUTI SUZUKI

THE GRAND VITARA

ASPIRION EDITION

Includes everything you aspire for.



BACK DOOR GARNISH

REAR LED GARNISH

REAR REFLECTOR GARNISH

HOOD EMBLEM

NOW AVAILABLE AT

₹13 99 900*

NEXA SAFETY SHIELD

SCAN TO CONNECT TO A SHOWROOM NEAR YOU

*Applicable T&C available at your nearest dealership. Ex-showroom price ₹13 99 900 for Grand Vitara Aspirion Edition, exclusively available in the Zeta (O) and Alpha (O) variants. Creative visualisation. Images used are for illustration purposes only. Features and accessories shown may not be part of the standard fitment. Black glass shade on the vehicle is due to lighting effect. Offers may vary and are subject to availability of stock. Maruti Suzuki India Limited reserves the right to discontinue an offer without further notice. Finance options available at the sole discretion of financier.

